एम. एम. एस ई : एच जीएएल, - याचिकाकर्ता।

बनाम:

सहगल पेपर्स लिमिटेड, - प्रतिवादी।

कंपनी आवेदन संख्या कंपनी याचिका में 1983 का 200

नहीं। 1983 का 97

23 अगस्त 1985

कंपनी अधिनियम (1956 का 1)—धारा 391, 392 और 394—कंपनी न्यायालय नियम, 11959—न्यायालय के आदेशों के तहत कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया–निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष ने धारा 391, 392 और 394 के तहत याचिका दायर की कंपनी को पुनर्जीवित करने की योजना पर विचार करने के लिए शेयरधारक और लेनदारों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश - सुरक्षित लेनदारों को छोड़कर सभी द्वारा अनुमोदित योजना - याचिकाकर्ता प्रस्तावित योजना की मंजूरी के लिए नियम 79 के तहत आवेदन कर रहा है - ऐसा आवेदन - क्या रखरखाव योग्य है - सुरक्षित लेनदारों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और मनमानी कार्रवाई के आरोप - कंपनी न्यायाधीश - क्या इस मामले में जाने का अधिकार क्षेत्र है।

निर्णय, कि कंपनी न्यायालय नियम, 1959 के नियम 79 को पढ़ने से पता चलेगा कि प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था की मंजूरी के लिए एक आवेदन केवल तभी स्वीकार्य है जब यह किया गया हो, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 की उप-धारा (2) के तहत अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित। यह धारा आगे यह स्पष्ट करती है कि प्रस्तावित व्यवस्था या समझौते की मंजूरी इसकी मंजूरी के लिए किसी भी आवेदन को आगे बढ़ाने से पहले एक शर्त है। . नियम 79 के खंड 4 द्वारा स्थिति को और स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि जहां समझौते या व्यवस्था की पुष्टि के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां समझौते या व्यवस्था को धारा 391(2) के तहत अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप पुष्टिकरण के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकी, पूर्ववर्ती नियम के तहत की गई बैठक के परिणाम के बारे में अध्यक्ष की रिपोर्ट को आवश्यक आदेशों के लिए कंपनी न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। जब तक न्यायालय के समक्ष लाई गई योजना को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक न्यायालय के पास इसकी मंजूरी के लिए नियमों के नियम 79 के तहत विचार करने और आवेदन करने या इस संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, भले ही योजना काफी उचित और लाभकारी पाई गई हो। उन लेनदारों के लिए जिन्होंने अपनी सहमति रोक रखी है।

निर्णय, कि कंपनी न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और सीमित है। कंपनी अधिनियम या नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कंपनी न्यायाधीश को सुरक्षित लेनदारों द्वारा सहमति को रोकने के मामले की जांच करने और यह मानने के लिए अधिकृत किया जाए कि यह दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से किया गया है। इसके अलावा, अगर यह पाया जाता है कि सहमति दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से रोक दी गई है, तो यह कंपनी न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से परे होगा या तो सुरक्षित लेनदारों द्वारा अस्वीकृति के बावजूद योजना को मंजूरी देना या उन्हें पुनर्विचार करने के लिए आदेश जारी करना वही और मंजूरी प्रदान करने के लिए. प्रस्तावित व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए अधिनियम की धारा 391 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए, यह एक शर्त है कि इसे धारा 391(2) में निर्धारित अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कंपनी जज के पास योजना को मंजूरी देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जब तक कि इसे धारा 391(2) में दिए गए अपेक्षित बहुमत से मंजूरी न मिल जाए।

(पैरा 6).

कंपनी न्यायालय नियमों के नियम 79 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

(i) मेसर्स सहगल पेपर्स लिमिटेड के सभी पसंदीदा लेनदारों, असुरक्षित लेनदारों, शेयरधारकों और सुरक्षित लेनदारों द्वारा समझौता या व्यवस्था की उक्त योजना को मंजूरी दी गई है। धारूहेड़ा, जिला मोहिंदरगढ़ (हरियाणा);

(ii) या ऐसा कोई अन्य आदेश याचिका की परिस्थितियों में किया जा सकता है जैसा न्यायालय उचित समझे।

(1) मेसमेसर्सगसहगलीपेपर्स (फॉर)आरटीशॉर्ट, 3 देम कंपनी), यूलिपु लिमिटेड कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया था, - आदेश, दिनांक 8 अप्रैल 1983, सी.पी. नहीं। 1981 के 64 और आधिकारिक परिसमापक को कंपनी के मामलों को संभालने और प्रबंधित करने का निर्देश दिया गया था। लगभग छह महीने बाद 15 सितंबर, 1983 को कंपनी के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष एम. एम. सहगल ने कंपनी याचिका संख्या दायर की। 1983 के 97 में कंपनी अधिनियम की धारा 391, 392 और 394 के तहत याचिका में विस्तृत व्यवस्था पर विचार करने के लिए विभिन्न लेनदारों और शेयरधारकों की एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। विद्वान कंपनी न्यायाधीश ने, दिनांक 27 सितंबर, 1983 के आदेशों के तहत, बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए श्री बी. और सभी शेयरधारकों ने एक ही तारीख, यानी 7 दिसंबर, 1983 को अलग-अलग हिस्सेदारी रखी। इस योजना को सुरक्षित लेनदारों को छोड़कर अन्य सभी द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। सुरक्षित लेनदारों द्वारा योजना की अस्वीकृति के बावजूद, याचिकाकर्ता ने इसकी मंजूरी के लिए कंपनी (न्यायालय) नियमों (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 79 के तहत यह आवेदन दायर किया। भारत संघ को एक नोटिस जारी करने और अखबारों में आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक उद्धरण प्रकाशित करने का आदेश दिया गया। केवल इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ही निर्धारित अवधि में आपत्तियां दाखिल कीं। इसके बाद, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दो आवेदन दायर किए, सी.ए. संख्या 1984 की धारा 36 एवं 37 विलंब क्षमा एवं स्थान की अनुमति हेतु, प्रस्तावित योजना पर आपत्तियाँ रिकार्ड में। इसी प्रकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ *पटियाला, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, श्रीमती। जनक कपूर और आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी आवेदन संख्या भी पेश की। उक्त योजना पर आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति हेतु 1984 के 27, 46, 50, 51, 53 एवं 151। इन सभी आवेदनों की सुनवाई मुख्य आवेदन के साथ करने का आदेश दिया गया. चूंकि अंतिम सुनवाई में उनके विरोध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई, इसलिए इन सभी आवेदनों को अनुमति दे दी गई और आपत्ति याचिकाओं को रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया गया।

(2) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर एम. एम. सहगल द्वारा एक प्रत्युत्तर दायर किया गया था, जिसके लिए कंपनी आवेदन संख्या दाखिल करना आवश्यक हो गया था। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा 1984 का 168। कोई विरोध न होने पर यह आवेदन भी मंजूर कर लिया गया। एम. एम. सहगल ने कंपनी आवेदन संख्या भी प्रस्तुत की। 1984 के 10 में आधिकारिक परिसमापक को कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया। मुख्य आवेदन के निस्तारण के साथ ही यह आवेदन निष्प्रभावी हो जायेगा और तदनुसार खारिज किये जाने का आदेश दिया जाता है। फिर भी एक और आवेदन, सी.ए. नहीं। 1984 का 186, एम, एम. सहगल द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए दायर किया गया था जिसका निपटान भी इस आदेश द्वारा किया जाएगा।

(2) (3) श्रीमान प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील घोष ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि कंपनी परिसमापन में है, प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था पर विचार करने के लिए बैठक आयोजित करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 391 के तहत एक आवेदन केवल आधिकारिक परिसमापक द्वारा ही सक्षम होगा। . अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने एस. के. गुप्ता और अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया। के. पी. जैन और अन्य, (1). -

(3) "* * * *

(4) इसके अलावा, धारा 391(1) स्वयं एक विशिष्ट और सकारात्मक प्रावधान द्वारा यह निर्धारित करती है कि इसके तहत कौन आवेदन दायर कर सकता है। किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में केवल ऋणदाता या उस

कंपनी का सदस्य या परिसमापक ही समझौते या व्यवस्था का प्रस्ताव करने वाला आवेदन दायर करने का हकदार है। आवश्यक निहितार्थ से, अनुभाग में निर्दिष्ट लोगों के अलावा कोई भी इस तरह के आवेदन को स्थानांतरित करने का हकदार नहीं होगा।

(1) (1979) 49 कैंप कैस। 342.

यह तर्क पूरी तरह से गलत है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्धरण जब इसके संदर्भ में पढ़ा जाता है तो इसका समर्थन नहीं करता है। धारा 391 (1) के प्रावधानों को उद्धृत किया गया था और उपरोक्त टिप्पणियों को यह स्पष्ट करने के लिए किया गया था कि धारा 392 के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति के संबंध में धारा में निहित सीमाएं धारा 392 के तहत आवेदन के संबंध में लागू नहीं थीं और कोई सवाल ही नहीं है। किसी कंपनी के परिसमापन की स्थिति में धारा 391(1) के तहत कौन आवेदन कर सकता है, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था। शब्द, "या किसी कंपनी के मामले में, जिसे परिसमापक द्वारा बंद किया जा रहा है" का मतलब यह नहीं है कि ऐसी कंपनी के मामले में, परिसमापक अकेले आवेदन को आगे बढ़ा सकता है और इसके बजाय परिसमापक को भी अधिकृत करने वाला एक सक्षम प्रावधान शामिल है। कंपनी के किसी भी लेनदार या सदस्य के अलावा, न्यायालय का रुख करें। इसी तरह का विचार त्रावणकोर कोचीन उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने मोहम्मद अब्दुल्ला और अन्य बनाम मामले में व्यक्त किया था। गोपाल पिल्लई और अन्य, (2) मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करते हुए: त्रावणकोर नेशनल 8जेड क्विलोन बैंक लिमिटेड (3), निम्नलिखित शब्दों में: -

"किसी कंपनी के बंद होने की स्थिति में, परिसमापक के शब्दों के परिचय का उद्देश्य एक अतिरिक्त व्यक्ति प्रदान करना है, न कि कोई विशिष्ट व्यक्ति जो आवेदन कर सके। यदि कोई कंपनी, या कोई सदस्य, या कोई लेनदार किसी ऐसी कंपनी के मामले में समझौता या व्यवस्था का प्रस्ताव करते हुए धारा 153(1) के तहत आवेदन कर सकता है जो परिसमापन के अधीन नहीं है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनमें से कोई भी सक्षम न हो ऐसी कंपनी के मामले में आवेदन करने के लिए जिसे बंद किया जा रहा है।"

इसलिए उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है।

(4) नियम ओ 79 के तहत आवेदन मंजूरी के लिए) सीप्रस्तावित पीकॉम मिस या व्यवस्था की जा सकती है यदि इसे कंपनी अधिनियम की धारा 391 की उप-धारा (2) के तहत अपेक्षित बहुमत से अनुमोदित किया गया है जो इस प्रकार है: -

"यदि संख्या में बहुमत लेनदारों, या लेनदारों के वर्ग, या सदस्यों, या जैसा भी मामला हो, सदस्यों के वर्ग के मूल्य में तीन चौथाई का प्रतिनिधित्व करता है, तो उपस्थित हों और मतदान करें

(2) ए.आई.आर. 1952 ट्र. कोचीन 243.

(3) ए.आई.आर. 1939 मैड. 318.

व्यक्तिगत रूप से या, जहां धारा 643 के तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रॉक्सी की अनुमति है, प्रॉक्सी द्वारा, बैठक में, किसी भी समझौते या व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की जाती है, समझौता या व्यवस्था, यदि अदालत द्वारा मंजूरी दे दी जाती है, तो सभी लेनदारों पर बाध्यकारी होगी। वर्ग के लेनदारों, सभी सदस्यों, या वर्ग के सभी सदस्यों, जैसा भी मामला हो, और कंपनी पर भी, या, किसी कंपनी के मामले में, जो बंद हो रही है, परिसमापक और योगदानकर्ता टोरीज़ पर कंपनी का।

बशर्ते कि किसी भी समझौते या व्यवस्था को मंजूरी देने वाला कोई भी आदेश अदालत द्वारा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अदालत संतुष्ट न हो जाए कि कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति जिसके द्वारा उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया गया है, ने हलफनामे या हलफनामे द्वारा अदालत को खुलासा किया है। अन्यथा, कंपनी से संबंधित सभी भौतिक तथ्य, जैसे कंपनी की नवीनतम वित्तीय स्थिति, कंपनी के खातों पर नवीनतम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, धारा 235 से 251 के तहत कंपनी के संबंध में किसी भी जांच कार्यवाही की लंबितता और इसी तरह ।"

उपरोक्त उप-धारा का एक मात्र अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि प्रस्तावित व्यवस्था या समझौते की मंजूरी इसकी मंजूरी के लिए किसी भी आवेदन को स्थानांतरित करने से पहले एक शर्त है। नियमों के नियम 79

के खंड 4 द्वारा स्थिति को और स्पष्ट कर दिया गया है, जिसमें प्रावधान है कि जहां समझौते या व्यवस्था की पुष्टि के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है या जहां समझौते या व्यवस्था को धारा 391(2) के तहत अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।) और परिणामस्वरूप पुष्टिकरण के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जा सकी, पूर्ववर्ती नियम के तहत की गई बैठक के परिणाम के बारे में अध्यक्ष की रिपोर्ट को ऐसे आदेशों के लिए न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा जो आवश्यक हो सकते हैं।

(5) श्रीमान श्री एलएच. आवेदक के प्रथम सलाहकार एस एल सिब्बल ने इस प्रस्ताव पर विवाद नहीं किया और न ही इस तथ्य पर विवाद किया कि प्रस्तावित व्यवस्था को धारा 391(2) के तहत आवश्यक सभी लेनदारों के अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने दो तर्क उठाने की मांग की। सबसे पहले, सुरक्षित लेनदारों के प्रतिनिधियों को बैठक में भाग लेने के लिए विधिवत अधिकृत नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा एसएचईएम की अस्वीकृति को सुरक्षित लेनदारों का कार्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि इस योजना का सुरक्षित लेनदारों द्वारा कभी विरोध नहीं किया गया है, यह माना जाएगा कि इस पर उनकी सहमति है। मैं इसकी सराहना करता हूं,विद्वान वकील के तर्क की सरलता लेकिन अधिनियम की धारा 391(2) के तहत प्रस्तावित समझौते या समझौते के निहित अनुमोदन की दलील देने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बजाय उक्त उपधारा स्पष्ट शब्दों में बताती है कि प्रस्तावित व्यवस्था या समझौते को लेनदारों के अपेक्षित बहुमत द्वारा एक सचेत कार्य द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि यह माना जाता है कि सुरक्षित लेनदार जो वित्तीय संस्थान हैं, उनका उचित रूप से अधिकृत एजेंटों द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, तो इसका परिणाम यह होगा कि प्रस्तावित व्यवस्था या समझौते की कोई मंजूरी नहीं थी और न ही यह कि उनके द्वारा इस पर अंतर्निहित सहमति दी गई थी। इसलिए, मुझे पहले तर्क को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(6) असली जोर श्री सिब्बल ने अपने दूसरे विचार पर दिया था कि वित्तीय संस्थानों द्वारा दुर्भावनापूर्ण और मनमाने ढंग से सहमति रोक दी गई थी। सार्वजनिक संस्थान और राज्य के साधन होने के नाते सुरक्षित ऋणदाता तर्कसंगत रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हैं और यदि वे अपने वैधानिक कार्यों को तर्कसंगत तरीके से करने में विफल रहते हैं तो न्यायालय योजना को मंजूरी देने या वैकल्पिक रूप से उन्हें आदेश जारी करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। मामले पर पुनर्विचार करें और अपेक्षित मंजूरी प्रदान करें। इस विवाद के लिए एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के बहुचर्चित मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया फैसले से समर्थन मांगा गया था। और दूसरा वी. भारत संघ और अन्य, (4). अपने तर्कों को विस्तृत करते हुए, उन्होंने आगे तर्क दिया कि सभी सुरक्षित ऋणदाता, जो या तो वैधानिक निगम या बैंकिंग संस्थान हैं, निदेशक मंडल की बैठक में अपना निर्णय ले सकते हैं और यही वह समय था जब उन्हें रोके जाने के कारण बताए जाने थे। सहमति नतीजतन, उनकी आपत्ति याचिकाओं में उनके द्वारा दिए गए कारण कोई फायदा नहीं दे सकते हैं और समर्थन में निर्भरता हो सकती है, जिसे मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम में सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित पारित होने पर रखा गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य, (5)। -

(6) "जब कोई वैधानिक पदाधिकारी कुछ आधारों के आधार पर कोई आदेश देता है, तो उसकी वैधता को उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और इसे हलफनामे या अन्यथा के रूप में नए कारणों से पूरक नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, शुरुआत में खराब आदेश, चुनौती के कारण अदालत में आने तक, बाद में लाए गए अतिरिक्त आधारों द्वारा मान्य हो सकता है।"श्रीमान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम को स्वीकार करना काफी कठिन है। सिब्बल ने इन कार्यवाहियों में भले ही तर्क के लिए यह मान लिया हो कि प्रस्तावित व्यवस्था की सहमति सुरक्षित लेनदारों द्वारा मनमाने ढंग से रोक दी गई है। कंपनी न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार कंपनी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और सीमित है। श्रीमान द्वारा कंपनी अधिनियम या नियमों में कोई प्रावधान नहीं बताया जा सका। न्यायाधीश को सुरक्षित लेनदारों द्वारा सहमति को रोकने के मामले की जांच करने और यह मानने के लिए अधिकृत किया कि यह दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से किया गया है। इसके अलावा, यदि यह पाया जाता है कि सहमति दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से रोक दी गई है, तो यह कंपनी न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र से पूरी तरह से परे होगा कि वह

सुरक्षित लेनदारों द्वारा अस्वीकृति के बावजूद योजना को मंजूरी दे या उन्हें पुनर्विचार करने का आदेश जारी करे। योजना और उनकी मंजूरी के अनुसार. श्री। . श्री। हालाँकि, सिब्बल ने तर्क दिया कि शक्ति उन कार्यों में निहित होगी जो एक कंपनी न्यायाधीश को करने हैं और अदालत सुरक्षित लेनदारों की सहमति से एक योजना को मंजूरी देने या उन्हें उस पर पुनर्विचार करने के लिए एक आदेश जारी करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगी और यदि योजना काफी उचित और संबंधित पक्षों के लाभ के लिए पाई जाती है, तो उन्हें मंजूरी दे दें। मेरे विचार में, विवाद पूरी तरह से किसी भी योग्यता से रहित है। जैसा कि प्रस्तावित व्यवस्था को मंजूरी देने के लिए अधिनियम की धारा 391 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करने के लिए पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, यह एक शर्त है कि इसे धारा 391(2) में निर्धारित अपेक्षित बहुमत द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। जब तक न्यायालय के समक्ष लाई गई योजना को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक उसे इसकी मंजूरी के लिए नियमों के नियम 79 के तहत किसी आवेदन पर विचार करने या इस संबंध में कोई आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, भले ही योजना काफी उचित और लाभकारी पाई गई हो। जिन लेनदारों ने अपनी सहमति रोक रखी है। इसी तरह का विचार मद्रास उच्च न्यायालय ने भी व्यक्त किया था। कोयंबटूर कॉटन मिल्स लिमिटेड और लक्ष्मी मिल्स कंपनी लिमिटेड, (6), जिसमें यह माना गया था कि यदि कोई वर्ग जिसके हित किसी योजना से प्रभावित हैं, धारा 391 के प्रावधानों के अनुसार बुलाई गई बैठक में इसे सहमति या अनुमोदन नहीं देता है, तो अदालत के पास इसकी पुष्टि करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। भले ही वह यह मानता हो कि संबंधित वर्ग के साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है या उन्हें योजना को मंजूरी देने का आदेश जारी करना होगा। हालाँकि मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय के पास योजना को मंजूरी देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है जब तक कि इसे अपेक्षित बहुमत से मंजूरी न मिल जाए।

(7) (6) (1980) 50 कैंप केस 623।

(8) जैसा कि अधिनियम की धारा 391(2) में प्रदान किया गया है या सुरक्षित लेनदारों को मामले पर पुनर्विचार करने और योजना को अपनी मंजूरी देने के लिए कोई निर्देश जारी करना है, फिर भी यदि ऐसा कोई उपाय खोजा जा सकता है तो यह केवल अनुच्छेद 226 के तहत ही संभव होगा। संविधान। एस्कॉर्ट लिमिटेड के मामले (सुप्रा) में निर्णय भी बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दिया गया था, न कि कंपनी अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। यहां तक कि उस मामले में निर्धारित नियम भी कि सार्वजनिक क्षेत्र के निगम द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर अदालत के पास पर्यवेक्षी शक्तियां होंगी, भी एक अत्यधिक संदिग्ध प्रस्ताव है और उक्त निर्णय के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही विशेष अनुमति में रोक लगा दी है। . इसलिए, मुझे इस तर्क में भी कोई योग्यता नहीं दिखती, जिसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

(7) इसके अलावा, 'गुण-दोष के आधार पर भी वर्तमान मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि वित्तीय संस्थानों ने दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से प्रस्तावित व्यवस्था से सहमत होने से इनकार कर दिया है। प्रारंभ में वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा दिया गया ऋण लगभग रु. 15 करोड़. अब तक यह रकम बढ़कर करीब 28 करोड़ हो गई है. प्रस्तावित योजना में रू. वर्ष 1998-99 तक 15 करोड़ रुपये की वार्षिक किस्त के माध्यम से भुगतान किया जाना है। 1.26 करोड़. वर्ष 1998-99 तक वित्तीय संस्थानों और बैंकों को देय राशि रु. 140 करोड़. रुपये का भुगतान. उनके लिए 15 करोड़ लगभग नगण्य होंगे। कंपनी की कुल संपत्ति अकेले जेएसईडी संस्थानों के प्रति उसकी देनदारियों से बहुत कम होगी। यदि योजना है; इसे मंजूरी देने का मतलब यह होगा कि वित्तीय संस्थानों और बैंकों का सारा सार्वजनिक धन भी डूबत ऋण बन जाएगा और उन संस्थानों को कुल नुकसान होगा। इस प्रकार वित्तीय संस्थानों को भुगतान का प्रस्ताव पूरी तरह से अपर्याप्त होने के कारण, वे संभवतः ऐसी किसी योजना पर सहमत नहीं हो सके। यदि वित्तीय संस्थान किसी न किसी कारण से ऐसी योजना के लिए सहमत भी हो जाते तो भी कोई अदालत उसे मंजूरी नहीं देती। योजना के अन्य प्रावधान भी सुरक्षित ऋणदाताओं के लिए अत्यधिक नुकसानदेह हैं, लेकिन उन पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रस्तावित व्यवस्था को अस्वीकार करने के लिए केवल उपरोक्त कारण ही पर्याप्त होगा। विद्वान वकील का यह तर्क कि सुरक्षित लेनदारों ने दुर्भावनापूर्ण या मनमाने ढंग से प्रस्तावित योजना की मंजूरी रोक दी है, का कोई आधार नहीं है और यह पूरी तरह से काल्पनिक है।

(8) इस स्थिति का सामना करते हुए, श्रीमान. सिब्बल ने आग्रह किया कि अदालत के पास अधिनियम की धारा 392 के तहत योजना को संशोधित करने और इसे व्यावहारिक बनाने के लिए पर्याप्त शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, योजना को लागू किया जा सकता है।उचित संशोधन के बाद मंजूरी दी जाएगी। मुझे डर है, इस न्यायालय के लिए ऐसा कोई उपाय अपनाना *अनुमति' नहीं है। जैसा कि धारा 392 के शुरुआती शब्दों से स्पष्ट है, उक्त धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब धारा 391 के तहत कोई समझौता या व्यवस्था स्वीकृत हो। यदि आवश्यकताओं की संतुष्टि न होने के कारण न्यायालय के समक्ष कोई वैध व्यवस्था नहीं है अधिनियम की धारा 391(2) के मामले में इसे न्यायालय द्वारा कभी भी मंजूरी नहीं दी जा सकती है और धारा 392 के लागू होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए, प्रस्तावित समझौते या व्यवस्था में किसी भी संशोधन का आदेश देना इस न्यायालय की क्षमता से परे होगा।

(9) ऊपर दर्ज कारणों से, इस आवेदन को लागत सहित खारिज किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र